International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 11 No. 5 May-June 2024

प्रतिदर्शी गाँवों का भौगोलिक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

कुलदीप कुमार ओझा[1], डॉ. ध्रुव कुमार द्विवेदी[2]
[1]शोधार्थी भूगोल, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.) भारत
[2]प्राचार्य सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
Corresponding Author: कुलदीप कुमार ओझा
DOI- 10.5281/zenodo.12704819

शोध सारांश :–

अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान है परन्तु यहाँ कृषि भूमि उपयोग में अत्याधिक क्षेत्रीय असन्तुलन पाया जाता है। तीव्रगति से बढ़ती जनसंख्या के कारण सबसे अधिक दबाव कृषि भूमि पर पड़ा है। बढ़ते दबाव और परिवर्तित हो रहे पर्यावरण के फलस्वरूप रीवा जिले की भूमि उपयोग परिवर्तनशीलता की प्रवृत्तियों का फसल प्रतिरूप पर पड़ने वाले प्रभावों का भौगोलिक अध्ययन करना इस शोध पत्र का मुख्य स्वरूप है एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द :–प्रतिदर्शी, गाँवों, भौगोलिक, अध्ययन, कृषि, भूमि, उपयोग, परिवर्तनशीलता आदि।

प्रस्तावना :–

भूमि एक मूलभूत प्राकृतिक संसाधन है जिस पर सामाजिक–सांस्कृतिक एवं अर्थिक कार्य सम्पन्न होते हैं। मानव समुदाय की तीन मूल–भूत आवश्यकताएँ –भोजन, वस्त्र व निवास जिसकी आपूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमि से ही प्राप्त होती है। भूमि को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या करने में भूगोलवेत्ताओं ने पर्याप्त कार्य किया है। सर्वप्रथम एल.डी. स्टॉम्प (1931) ने ब्रिटेन के भूमि उपयोग सर्वे करवाया था। जिसमें उन्होंने भूमि को सात वर्गो में बांटा– कृषि भूमि, ऊसर, चारागाह, बाग, नर्सरी, घास–स्थली, जंगल और नगर क्षेत्र के अधीन भूमि। इस भूमि वर्गीकरण को स्टॉम्प ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक ''The Land of Britain its use and Misuse'' विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया है। **भारत के संदर्भ रॉव (1947), सिन्हा (1968), बी.आर. सिंह (1970)** आदि ने भूमि उपयोग के विभिन्न पक्षों से संबंधित अध्ययन का विशेष योगदान रहा है। भूमि उपयोग, जनसंख्या का घनत्व, सिंचाई की आधुनिक सुविधा, भू–स्वामित्व का प्रारूप, प्राविधिक एवं हरितक्रान्ति ने अत्यन्त प्रभावित किया है। रीवा जिले में भूमि उपयोग का वर्तमान स्वरूप भूमि संसाधन का काल–क्रमिक उपयोग पर आधारित है। बाणसागर सागर एवं सोन नदी के कारण सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मानव ने अपनी तकनीक विकास जैविक उर्वरकों के उपयोग, कृषि अयोग्य भूमि को कृषिगत भूमि में परिवर्तित होने, ऊसर सुधार और नदियों एवं भूमिगत जल संसाधनों के अधिक उपयोग होने से आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से भूमि संसाधन का सर्वाधिक उपयोग कृषक करने लगा है।

भूमि उपयोग एवं गत्यात्मक तत्व है जो भौतिक दशाओं में परिवर्तन तथा मानव के सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के अनुरूप परिवर्तित, परिष्कृत एवं परिमार्जित होता रहता है। यही कारण है कि किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग उस क्षेत्र में निवास करने वाले मानव की बौद्धिक क्षमता तथा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास स्तर का सूचक होने के साथ–साथ उस क्षेत्र में व्याप्त भौतिक वातावरण का निरूपक भी होता है।

भूमि उपयोग वैज्ञानिक युग की उपलब्धियों से पूर्णतः प्रभावित है। वेनजेट्टी के अनुसार– ''भूमि उपयोग प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक उत्पादनों के संयोग का प्रतिफल है।'' जब तक किसी क्षेत्र विशेष में भूमि उपयोग प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं के अनुरूप रहता है। अर्थात् मानवीय क्रिया–कलाप, प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है तब तक भूमि का आर्थिक महत्व कम एवं जन–जीवन का स्तर निम्न होता है। कालक्रम में जब भूमि उपयोग प्रारूप के निर्धारण में मानवीय भूमि निर्णायक हो जाती है एवं भूमि उपयोग में आर्थिक संसाधनों का विनियोजन अधिक होने लगता है तब उस अवस्था में भूमि की संसाधन में वृद्धि हो जाती है और जन–जीवन का आर्थिक स्तर अपेक्षाकृत उच्च हो जाता है।

शोध वह सम्बद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन–विधि है जिसके आधार पर घटनाओं के सम्बन्ध में हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं या विद्यमान ज्ञान को विस्तृत या परिष्कृत करते हैं एवं विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धों की व उपलब्ध सिद्धान्तों की पुनः परीक्षण करते हैं और भी संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि घटनाओं या विद्यमान सिद्धान्तों के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक विधि ही शोध प्रविधि है।

शोध, वैज्ञानिक अनुसन्धान का ही एक विशेष रूप है जिसका सम्पर्क तथ्यो, घटनाओं, मानवीय क्रियाकलापों तथा उसमें पाए जाने वाले अन्तः सम्बन्धों से होता है। शोध जीवन के सम्बन्ध में सत्य की खोज करने की एक वैज्ञानिक विधि है। निम्नलिखित परिभाषाओं से यह बात और भी स्पष्ट हो सकेगी।

शोध कार्य के दौरान शोधार्थी द्वारा कुछ चिन्हित गाँवों की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर जानकारी एकत्रित किया है जो इस प्रकार है–

1. लालगाँव–

यह ग्राम पंचायत मुख्यतः मनगवां तहसील के अंतर्गत शामिल है, विभिन्न अध्ययनों एवं रीवा राज्य दर्पण के आलेखों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक दिनों में इस गाँव की न्यूनतम आबादी रही है। किंतु धीरे–धीरे जनसंख्या का विस्तार हुआ तथा इस गाँव में छोटे–छोटे व्यापारिक केन्द्रों के कारण आबादी दिनों–दिन बढ़ती गई।

इस ग्राम पंचायत में शासकीय महाविद्यालय एवं निजी महाविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान होने कारण

आस–पास के क्षेत्रों से भी जनसंख्या का दबाव उन्नतोदर वृद्धि हुई है।

इस ग्राम पंचायत के विकास का मुख्य स्वरूप परिवहन मार्गों से सीधा जुड़ाव है जिसमें रीवा से कटरा एवं सिरमौर मुख्य मार्ग के निर्माण से अनेकों व्यापारिक गतिविधियों को बड़ी सरलता के हुआ है जिसके फलस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि होना लाजमी है।

स्थिति एवं विस्तारः– लालगाँव रीवा जिले के सिरमौर तहसील में 24-1184 N $24^0$48*42-62184** उत्तरी अक्षांश एवं 81052124 E $81^0$31'16.4676'' पूर्वी देशांतर पर स्थित एक ग्राम पंचायत है। पटवारी अभिलेख के अनुसार 284.25 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। वर्ष 2011 के जनसंख्या जनगणना पुस्तिकानुसार कुल जनसंख्या 7939 जिसमें 4099 पुरुष एवं 3840 महिला जनसंख्या है तथा इस ग्राम में 1724 परिवार निवास करते हैं।

लालगाँव ग्राम पंचायत में पशुपालन कृषि के लिये एक महत्वपूर्ण सहायक अर्थव्यवस्था के रूप में किया जाता है क्योंकि कृषि कार्य के पशुपालन एक मुख्य घटक माना जाता है। इस ग्राम में कुल पशुओं की संख्या 428 है जिनमें 240 गोवंशीय, 90 भैसवंशीय तथा शेष अन्य पालतू पशु हैं।

इस ग्राम में चावल, गेहूं, दलहन/तिलहन जैसी फसलें तथा साग, सब्जी आदि का उत्पादन किया जाता है।

उपयोग सारणी क्रमांक 1
लालगाँव ग्राम पंचायत का भूमि

क्र0	विवरण	प्रयुक्त क्षेत्रफल	प्रतिशत में
1.	वन	16	9.94
2	बंजर गोचर	21	6.32
3	पड़ती	25	5.35
4	कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि	11	11.88
5	कृषित भूमि		
अ	एक फसली	14	2.85
ब	द्वि फसली	25	5.88
	योग–	284.25	100

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 01 से स्पष्ट होता है कि लालगाँव में भूमि उपयोग जिसका कुल क्षेत्रफल 284.25 हेक्टेयर है जिसमें वन भूमि 09.94 प्रतिशत, बंजर गोचर भूमि 06.32 प्रतिशत, पड़ती भूमि 05.35 प्रतिशत, कृषि के लिये अनुपलब्ध भूमि 11.88 प्रतिशत तथा कृषित भूमि 57.78 प्रतिशत जिसमें एक फसली 02.85 प्रतिशत, द्विफसली 05. 88 प्रतिशत भूमि उपलब्ध है।

अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भूमि उपयोग ये कृषित भूमि का रकवा सर्वाधिक होने के बाद भी एक फसली एवं द्विफसली भूमि का अनुपात कम है।

सारणी क्रमांक 2
लालगाँव ग्राम पंचायत में उत्पादित फसल एवं उत्पादन का प्रतिशत

क्र0	फसल का नाम	उत्पादित फसल(क्विंटल में)	उत्पादित फसल का प्रतिशत
1	गेहूँ	350.01	27.07
2	चावल	281.25	30.47
3	तिलहन	7	0.75
4.	दलहन	50	5.42
5	चना	115	23.28
6	अन्य	120	12.99
	योग	923.35	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत लालगाँव में उत्पादित फसल में सर्वाधिक तौर में चावल की फसल जिसका उत्पादन का प्रतिशत 30.17 एवं गेहूँ 27.07 तथा चना 23.28 एवं तिलहन 0.75, दलहन 5.42 की पैदावार लालगाँव पंचायत में उत्पादित फसल की निरंतर वृद्धि हो रही है जिससे कृषकों के आय में वृद्धि हुई है।

अर्थव्यवस्था– इस ग्राम पंचायत में रहने वाली आबादी जनसंख्या अनेक उद्यमों में संलग्न है। कार्यशीलता की दृष्टि से जनसंख्या अलग–अलग कार्यों से संबंधित है।

सारणी क्रमांक 3
लालगाँव ग्राम पंचायत का व्यावसायिक स्वरूप

क्र.	विवरण	कुल कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत
1	कृषक	1421	6.70
2	कृषि मजदूर	1627	27.05
3	शिल्पकला	101	1.69
4	पशुपालन	380	6.33
5	अन्य	3486	57.95
	योग	6015	100

लालगाँव ग्राम पंचायत का व्यावसायिक स्वरूप –

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि लालगाँव ग्राम पंचायत में व्यावसायिक स्वरूप में कार्यशील जनसंख्या जिसमें कृषकों का 6.70 प्रतिशत भागीदारी है एवं कृषि मजदूर 27.05 प्रतिशत, शिल्पकला 1.69 प्रतिशत तथा पशुपालन 6.33 प्रतिशत एवं अन्य में 57.95 प्रतिशत लोग संलग्न हैं।

अतः ग्राम पंचायत में कार्यशील जनसंख्या को इतनी बड़ी आबादी के लिये शासन के द्वारा रोजगार के लिये ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। जिससे आज भी युवा वर्ग कृषि कार्यों से दूर होता जा रहा है तथा वो किसी अन्य शहर के लिये पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है।

शासन प्रशासन को रोजगार के लिये स्थानीय लोगों को कोई ठोस कदम उठाया जाये जिससे लोगों में जीवन स्तर में सुधार हो सके।

2. ग्राम पंचायत हरदोली

स्थिति एवं विस्तार –

यह ग्राम पंचायत रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत शामिल है जो तराई अंचल में जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट से लगती है तथा यह पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वहां से 15 किमी की दूरी पर डभौरा रेलवे स्टेशन है जो रीवा जिले का प्रथम रेलवे स्टेशन माना जाता है। मानिकपुर जंक्शन से प्रयागराज जंक्शन रूट में यह स्टेशन स्थित है। जिसमें अनेक छोटी–बड़ी ट्रेनों का ठहराव होता है जो लोगों को देश के कोने–कोने से जोड़ने के लिये परिवहन का एक सशक्त माध्यम है।

जिसका अक्षांशीय एवं देशान्तरीय विस्तार– 24. 9639एन24^{0}57′50.02956′′एवं 81.49037 ई8129′25.32588′′ है। यहाँ की धरातलीय स्वरूप में असमानता है कुछ क्षेत्रों में समतल एवं कुछ जगह में ढालयुक्त है। मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ एवं बलुई प्रकार पाई जाती है। यहाँ की मुख्य फसल धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सरसो आदि की पैदावार की जाती है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 731 हे0 है।

यह एक पिछड़ा क्षेत्र है जो औद्योगिक रूप से बहुत पीछे है तथा रोजगार एवं जीविकोपार्जन हेतु लोगों को बाहर जाकर अपना भरण–पोषण करना पड़ता है।

सर्वेक्षण के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर आवारा पशुओं एवं जंगली जानवरों से खेती को नुकसान पहुंचाया जाता है। जिससे वहां के कृषि कार्यों लगे लोगों में आक्रोश व्याप्त है जिसमें शासन प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिससे कृषि कार्य को बढ़ावा मल सके एवं आर्थिक संकट का दबाव कम हो सके।

साथ ही सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता अति–आवश्यक है। इस ग्राम पंचायत में कुल आबादी 2761 है जिसमें 1444 पुरुष एवं 1317 महिला जनसंख्या है एवं 541 परिवार निवासरत हैं।

यहाँ से 1 किमी0 की दूरी पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमान मंदिर है जिसे 'दुअरानाथ' के नाम से जाना जाता है। जहां पर प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ होती है तथा श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार/शनिवार में वृहद मेला लगता है। इसकी अपनी अलग सौन्दर्यता है पहाड़ी भाग से जुड़ा हुआ यह स्थान एवं प्राकृतिक वनस्पतियां इस स्थल के खूबसूरती को और बढ़ाती हैं।

सारणी क्रमांक 4
ग्राम हरदोली का भूमि उपयोग

क्र0	विवरण	प्रयुक्त क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल
01	वन	98.16	13.40
02	बंजर गोचर	104.08	14.28
03	पड़ती भूमि	96.7	13.22
04	कृषि के लिए अनुपलब्ध	100.19	13.70
05	कृषित भूमि		
अ	एक फसली	260.41	35.62
ब	द्विफसली	71.46	10.78
	कुल योग	**731**	**100**

उपरोक्त तालिका क्र0. 4 से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत हरदोली जो जवा तहसील के अंतर्गत शामिल पंचायत है। जिसका भौगोलिक कुल क्षेत्रफल 731 हेक्टेयर है जिसका भूमि उपयोग अलग–अलग वर्गों में विभाजन किया गया है जो निम्न प्रकार है– जिसमें वन भूमि 13.40 प्रतिशत, बंजर गोचर 14.28 प्रतिशत एवं पड़ती भूमि 13.22 प्रतिशत, कृषि के लिये अनुपलब्ध 13.70 कृषित भूमि 46.40 जिसमें एक फसली भूमि 35.62 तथा द्विफसली भूमि का क्षेत्रफल 9.78 है।

अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत हरदोली जो एक पिछड़ा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है जिसमें आधारभूत संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण कृषि उत्पादकता में कमी है तथा शासन को सिंचाई सुविधाएँ इन क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की सख्त आवश्यकता है। जिससे कृषि कार्यों में संलग्न परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके जिससे समाज में कल्याण के लिए एक सार्थक प्रयास होगा। गाँव विकसित होगा तभी राष्ट्र विकसित होगा, क्योंकि भारत गाँवों का देश है। एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं।

अर्थव्यवस्था –

यह ग्राम मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। इसके बावजूद भी आर्थिक गतिविधियों का कोई विशेष साधन नहीं है। गाँव में घरेलू उपयोग सम्बन्धित सामग्रियों को दैनिक उपभोग के लिये छोटी–छोटी दुकानें स्थापित हैं तथा लोगों के रोजगार के लिये औद्योगिक कारखानों का अभाव है, जिससे पंचायत में रहने वाली एक बड़ी आबादी बेरोजगार है। लोगों का मुख्य काम खेती में काम करना जो एक मौसमी बेरोजगारी को कम करता है शेष समय में आर्थिक संकट बना रहता है। ग्राम पंचायत में संलग्न जनसंख्या का व्यावसायिक स्वरूप इस प्रकार है–

सारणी क्रमांक 5
ग्राम पंचायत हरदोली में संलग्न जनसंख्या

क्र0	विवरण	कुल कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत
1	कृषक	450	17.96
2	कृषि मजदूर	1020	40.72
3	शिल्पकला	120	4.79
4	पशुपालन	200	7.98
5	अन्य	715	28.55
	योग	2505	100.00

स्त्रोत– क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित

उपरोक्त सारणी क्र. 5 से स्पष्ट होता है कि ग्राम हरदोली में विभिन्न कार्यों में लगी कार्यशील जनसंख्या जिसको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है जो इस प्रकार है–

जिसमें कृषकों की भागीदारी 17.96 प्रतिशत है एवं कृषि मजदूर 40.72 प्रतिशत, शिल्पकला 4.79 प्रतिशत एवं पशुपालन 7.98 प्रतिशत तथा गाँव में अन्य कार्यों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत 28.55 है। निष्कषतः कहा जा सकता है कि यह गाँव तराई अंचल का पिछड़े क्षेत्रों में शामिल है। जिसमें लोगों के लिये रोजगार के नये अवसर की आवश्यकता है जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

सारणी क्रमांक 6
ग्राम हरदोली में उत्पादित फसल का विवरण

क्र0	फसलों के नाम	उत्पादित फसल (क्विंटल में)	उत्पादन का प्रतिशत
1	गेहूं	2078.05	41.74
2	चावल	2150.00	43.20
3	तिलहन	75.00	1.50
4	दलहन	140.00	2.81
5	चना	120.00	2.41
6	अन्य	415.00	8.34
	योग	4978.05	100

उपरोक्त सारणी क्रं0 6 से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत हरदोली में कुल कृषि भूमि में उत्पादित फसलों का विवरण दिया गया है जो इस प्रकार है– जिसमें गेहूं 41.74 प्रतिशत, चावल 43.20 प्रतिशत, तिलहन 1.50 प्रतिशत, दलहन 2.81 प्रतिशत, चना 2.41 प्रतिशत एवं अन्य फसलें 8.34 प्रतिशत है।

निष्कर्ष में कह सकते हैं कि सर्वाधिक तौर पर चावल की पैदावार की जाती है क्योंकि ये खरीफ की फसल है इसमें प्राकृतिक रूप से वर्षा के कारण जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां पर भी प्रकृति आधारित फसलोत्पादन किया जाता है तथा मध्यम क्रम से गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है एवं सबसे कम तिलहन की पैदावार की जाती है। कृषि कार्य को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

3. ग्राम पंचायत बेलवा पैकान

स्थिति एवं विस्तार –

यह ग्राम पंचायत मनगवां तहसील के अंतर्गत शामिल है। जिसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार 24.63 एन 24^0.37′58′′ एवं 81.50 ई $81^0$30′32′′ इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 879.82 हे0 है। जिसकी कुल जनसंख्या 4818 जिसमें पुरुषों की संख्या 2480 एवं महिलाओं की संख्या 2338 है एवं कुल परिवारों की संख्या 916 है। इस ग्राम पंचायत में कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या 3066 है जिसमें पुरुषों की संख्या 1785 एवं महिलाओं की संख्या 1281 है। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 730 है एवं अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 505 है।

यह ग्राम पंचायत मुख्य रूप से समतल मैदान भू–भाग के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र की मृदा मुख्य रूप से काली/दोमट प्रकार की है। इस ग्राम में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। साथ ही कृषकों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। इस ग्राम में खरीफ फसलों में धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तुअर आदि फसलें उत्पादित की जाती हैं एवं रबी फसलों में मुख्यतः गेहूं, चना, मसूर, सरसों एवं अलसी आदि फसलें बहुतायत में उत्पादित की जाती हैं।

परिवहन के साधनों में यह ग्राम मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.–135 से जुड़ा हुआ है एवं ग्राम पंचायत से अन्य प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा जोड़ा गया है। जिसमें आवागमन के साधन की सुलभता बनी हुई है तथा कुछ भागों में अभी भी कच्ची सड़कें ही आवागमन का माध्यम बनी हुई है।

कृषि कार्य में सिंचाई प्रयुक्त साधनों में नहरें, ट्यूबवेल व नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। वर्तमान समय में ग्राम में जल स्तर कम होता जा रहा है जो चिंता का विषय है।

सारणी क्रमांक 7
ग्राम बेलवापैकान का भूमि उपयोग

क्र0	विवरण	प्रयुक्त क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल प्रतिशत
1	वन	70.25	7.98
2	बंजर गोचर	150.12	17.06
3	पड़ती भूमि	125.15	14.22
4	कृषि के लिए अनुपलब्ध	175.80	19.98
5	कृषित भूमि		
अ.	एक फसली	305.50	34.72
ब.	द्विफसली	53.00	6.02
	कुल	879.82 हे0	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक 6.7 से ज्ञात होता है कि प्रतिदर्शी ग्राम पंचायत बेलवा पैकान में कुल भूमि 879.82 हेक्टेयर में अनेक फसलोत्पादन एवं अन्य में भूमि उपयोग किया जा रहा है जिसमें वन 7.98 प्रतिशत, बंजर गोचर 17. 06 प्रतिशत, पड़ती भूमि 14.22 प्रतिशत एवं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 19.98 प्रतिशत तथा कृषित भूमि का उपयोग 40.74 प्रतिशत पर की जाती है जिसमें एक फसली भूमि का उपयोग 34.72 प्रतिशत तथा द्विफसली भूमि उपयोग 6.02 प्रतिशत पर की जाती है।

अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में सिंचाई साधनों की उपलब्धता के कारण कृषि क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। तथा आज आधुनिक तकनीकि ने भी कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

गाँव में खरीफ एवं रवी की फसलें मुख्यतः उगाई जाती है तथा गर्मी के दिनों में जायद की भी फसल कुछ भागों में उत्पादन किया जाता है। जिनसे कृषि कार्यों में लगे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। कृषि को एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाना पड़ेगा जिससे यह गाँव ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण जिला खाद्यान्न उत्पादन में सर्वोपरि बन सके।

अर्थव्यवस्था –

इस ग्राम में कृषि कार्यों के लिये मुख्य रूप से रबी एवं खरीफ तथा जायद की फसलें पैदावार की जाती हैं। यह ग्राम जिला मुख्यालय से 25 किमी0 की दूरी पर स्थित होने के कारण श्रमिक वर्ग प्रतिदिन परिवहन के साधनों से अपने जीविकोपार्जन के लिये काम करते हैं। जिसमें कुशल एवं अकुशल श्रमिक शामिल होते हैं जो मकानों के निर्माण तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में श्रम का कार्य किया जाता है। उससे मिलने वाले पारिश्रमिक से अपने घर– परिवार के भरण–पोषण की व्यवस्था की जाती है।

इस गाँव में लघु एवं सीमान्त कृषकों की उपलब्धता है जिसमें लोगों के साथ कृषि कार्य के लिये छोटे–भूखण्ड हैं एवं गाँव के कुछ हरिजन/आदिवासियों के पास आवास के अतिरिक्त कोई भूखण्ड नहीं है। गाँव में दैनिक जीवन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएँ छोटे–छोटे दुकानदारों के माध्यम से उपलब्ध हो पाती है।

ग्राम में प्राथमिक पाठशाला से माध्यमिक विद्यालय तक के संस्थान स्थापित हैं एवं महिला बाल विकास के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं उप–स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन किया जाता है एवं ये बुनियादी सुविधाएँ मानव स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए आय जनमानस के लिए उपलब्ध है। जिसमें 0–6 वर्ष तक के शिशु एवं गर्भवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं से स्वास्थ्य संबंधी दवाएँ, जाँच और टीकाकरण एवं पूरकपोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। इस गाँव में स्थानीय उद्योगों के अभाव में रोजगार एक बड़ी समस्या है।

सारणी क्रमांक 8
विभिन्न कार्यों में संलग्न जनसंख्या

क्र0	विवरण	कुल कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत
1	कृषक	680	16.92
2	कृषि मजदूर	1300	32.36
3	शिल्पकला	175	4.35
4	पशुपालन	450	11.20
5	अन्य	1413	35.17
	योग	4018	100

स्त्रोत– क्षेत्रीय सर्वेक्षण

बेलवा पैकान की कार्यशील जनसंख्या का विवरण –

उपरोक्त सारणी क्र0 8 से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत बेलवा पैकान में कुल जनसंख्या जिसमें कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या 16.92 प्रतिशत, कृषि मजदूर 32.36 प्रतिशत, शिल्पकला 4.35, पशुपालन 11.20 एवं अन्य कार्यों में संलग्न 35.17 प्रतिशत लोग कार्य कर रहे हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में लोग अब गाँवों से स्थानीय शहर या किसी अन्य प्रान्त में रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। जिसको रोकने के लिए सरकार को स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे।

सारणी क्रमांक 9
बेलवा पैकान में उत्पादित फसल का विवरण

क्र0	फसलों के नाम	उत्पादित फसल (क्विंटल में)	उत्पादन का प्रतिशत
1	गेहूं	1395	25.97
2	चावल	2525	47.03
3	तिलहन	310	5.77
4	दलहन	740	13.79
5	अन्य	400	7.44
	योग	5370	100

उपर्युक्त सारणी क्र0 .9 से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत बेलवा पैकान में कुल कृषि में उत्पादित फसल जिसमें गेहूं 25.97 प्रतिशत, चावल 47.03 प्रतिशत, तिलहन 5.77 प्रतिशत, दलहन 13.79 प्रतिशत एवं अन्य फसलें 7.44 प्रतिशत उत्पादित की जाती हैं जिसमें सर्वाधिक उत्पादन चावल की फसल का है एवं सबसे न्यूनतम तिलहन की फसल है।

वर्तमान परिस्थितियों में भूमि उपयोग में कारण फसल प्रतिरूप पर अनेकानेक परिवर्तन हुए हैं। जिसमें सिंचाई के साधन एवं वैज्ञानिक तकनीक आदि कारक शामिल हैं।

सुझाव :–

1. जिले के ग्रामीण अंचल तहसील स्तर पर एक तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना होने की आवश्यकता है जिससे उच्च शिक्षा में छात्रों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा हो सके।
2. तहसील मुख्यालयों पर कृषि प्रशिक्षण केन्द्र तथा उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर कृषकों एवं छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान सुलभ कराया जा सकता है जिसके माध्यम से आने वाले समय में विद्यार्थियों को कृषि कार्यों में रुचि बढ़ेगी जो राष्ट्र के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।
3. जिले के ग्रामीण अंचलों में प्रकाश एवं पेयजल की पूर्ति हेतु विद्युत विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग योजनाबद्ध तरीके से वर्ष 2030 तक शत–प्रतिशत पूर्ति हेतु तत्परता से प्रयास किया जाय जिससे पिछड़े क्षेत्रों को भी विकास की बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जा सके जिससे समाज के पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में अग्रसर हो सकें।
4. वर्तमान समय में प्रत्येक ग्रामों में महिला बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जिसमें आंगनबाड़ी/आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा शिशु एवं गर्भवती महिला, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी जागरूकता से सुधार देखने को मिला है। अभी इस सम्बन्ध में और उत्कृष्ट कार्य करने की आवश्कयता है।
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रस्तावित शैययाओं की पूर्ति करते हुये डाक्टर, नर्स एवं कम्पाउण्डर को समुचित सेवायें उपलब्ध कराई जाए जिससे आम लोगों तक लाभ पहुँच सके।
6. प्रत्येक ज्यादा आबादी वाले ग्रामों में बाल–विकास संस्थान तथा प्रसूति गृह की स्थापना की जानी चाहिये।
7. जिले के तहसील मुख्यालयों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सिविल हॉस्पिटल में परिवर्तित कर दिया जाय। जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो सके।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु चल चिकित्सालयों का अधिकाधिक विकास किये जाने की आवश्यकता है।
9. जिले में औद्योगिक विकास में वृद्धि के साथ–साथ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में भी वृद्धि हो रही है लोगों को पर्यावारण प्रदूषण से होने वाली गम्भीर बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को जनजागरूकता की अतिआवश्यकता है।

निष्कर्षतः

यह कहा जा सकता है कि देश में भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है फिर भी समग्र कृषि भूमि में सुधार की जो पहल हो रही है वास्तव में उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है, जिसका लाभ कृषि कार्यों में संलग्न कृषक परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है।

संदर्भ स्रोत :–

1. गुर्जर, अर.के. एवं जाट, वी.सी. (2002) संसाधन एवं पर्यावरण।
2. एस.के. ओझा (2013–14) सामान्य अध्ययन विशेषांक, पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण, प्रकाशन प्रयाग राज (परीक्षा वाणी)।
3. नायक डॉ. शशि किराण 2011) मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
4. मो0 हारून (2006) संसाधन भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर।
5. प्रमिला कुमार एवं श्रीकमल शर्मा (2016) कृषि भूगोल , मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
6. मामोरिया डॉ. चतुर्भुज (2019) जनसंख्या भूगोल, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।